



# छत्तीसगढ़ में नवीन शहरी मिशन की कल रायपुर में समीक्षा की जाएगी

## 19 राज्यों में अब तक 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाले मिशनों की समीक्षा का कार्यान्वयन

### श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा, समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में उच्चस्तरीय समीक्षा

Posted On: 25 MAY 2017 4:17PM by PIB Delhi

पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में शुरू हुए नवीन शहरी मिशनों की प्रगति की समीक्षा कल रायपुर में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में की जाएगी।

केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, राज्य के संबंधित मंत्री, केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मिशन निदेशक विभिन्न मिशनों के कार्यान्वयन और प्रगति के बारे में चर्चा के लिए आयोजित बैठक में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ में पांच शहरी मिशन अर्थात् कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (एमआरयूटी), स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और दीन दयाल अन्त्योदय योजना - एनएलयूएम की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।

नवीन शहरी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पहल के तहत श्री एम. वेंकैया नायडू विभिन्न परियोजनाओं के लिए मंजूर कुल 04 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से 19 राज्यों में 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संबंधित राज्य की राजधानियों में समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इस क्रम में, छत्तीसगढ़ 20वां राज्य होगा, जहां इन परियोजनाओं की प्रगति एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

पिछले तीन महीनों के दौरान अब तक जिन राज्यों में समीक्षा का यह कार्य पूरा किया जा चुका है उनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

मेट्रो आदि परियोजनाओं को जहां कहीं भी क्रियान्वित किया जा रहा है, वहां मेट्रो परियोजनाओं और विरासती बुनियादी ढांचों के विकास संबंधी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

इन समीक्षा बैठकों का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को छोड़कर बाकी सभी परियोजनाएं जो विभिन्न राज्यों में शहरी नवीनीकरण के लिए चल रही हैं, उनका समयबद्ध तरीके से 2019-20 तक कार्यान्वयन और उनको पूरा करना है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रत्येक शहरी गरीब योग्य लाभार्थी को 2022 तक खुद का घर उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है। प्रत्येक समीक्षा बैठक चार घंटे से भी अधिक समय तक चलती है।

छत्तीसगढ़ में होने वाली समीक्षा बैठक से पूर्व, श्री वेंकैया नायडू ने आज कहा कि वह 19 राज्यों में की गई उपयोगी समीक्षा बैठकों से काफी खुश हैं। ये बैठकें केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई हैं।

\*\*\*

जीवाई/प्रवीन/एमएम- 1477

